सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 285 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 29 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

भिलाई निगम के अपर आयुक्त का आदेश भी बेअसर!

10 दिन में सूचना देने के निर्देश के बाद भी नहीं मिली आरटीआई की जानकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। निगम के अपर आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बावजूद आज तक आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह मामला न केवल सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाता है, बल्कि निगम के भीतर प्रशासनिक जवाबदेही और अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों के पालन को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

मामला आरटीआई आवेदक द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई से मांगी गई जानकारी से जुड़ा है। उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को आवेदन प्रस्तुत कर शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और पोस्टरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं।

समय पर सूचना नहीं मिली तो करनी पड़ी प्रथम अपील

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आवेदक ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील क्रमांक 69/2026 पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुख्य कार्यालय द्वारा आवेदन संबंधित राजस्व विभाग को भेजा गया था, जबकि राजस्व विभाग ने जानकारी जोन-01, जोन-02, जोन-03, जोन-04 एवं जोन-05 से संबंधित बताते हुए सभी जोन आयुक्तों को पत्र भेजने की बात कही। रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य कार्यालय की ओर से जानकारी प्राप्त करने के लिए 16 अप्रैल 2026 को राजस्व अधिकारी को पत्र भेजा गया। इसके बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर 15 मई 2026 को स्मरण पत्र (रिमाइंडर) भी जारी किया गया। इसके बावजूद संबंधित जोनों से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

छः बिंदुओं पर मांगी गई थी महत्वपूर्ण जानकारी

- भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में स्वीकृत होर्डिंग, यूनिपोल एवं पोस्टरों की कुल संख्या।
- प्रत्येक स्वीकृत होर्डिंग एवं यूनिपोल का स्थान, आकार, स्वीकृति की तिथि तथा जारी लाइसेंस/अनुमति की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर लगाए गए जुर्माने की वर्षवार जानकारी।
- पिछले तीन वर्षों में अवैध होर्डिंग एवं पोस्टरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण।
- वर्तमान में चिन्हित अवैध होर्डिंग एवं पोस्टरों की संख्या तथा उनके विरुद्ध प्रस्तावित अथवा लंबित कार्रवाई।
- होर्डिंग लगाने से संबंधित निगम के नियम, उपविधियां (By-laws) एवं दिशा-निर्देशों की प्रति।

ये सभी जानकारियां सार्वजनिक महत्व की हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध नगर निगम की राजस्व व्यवस्था, शहरी सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।

सुनवाई में अधिकारियों ने स्वीकार की जानकारी उपलब्ध न होने की बात

प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान आवेदक ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद से उन्हें आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सुनवाई में उपस्थित सहायक जनसूचना अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। वहीं, राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि सभी जोन आयुक्तों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है और जानकारी प्राप्त होने के बाद ही आवेदक को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अपर आयुक्त ने दिए थे स्पष्ट निर्देश

दोनों पक्षों की बात सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अपर आयुक्त सह प्रथम अपीलीय अधिकारी राजेन्द्र कुमार दोहरे ने स्पष्ट आदेश पारित किया कि जनसूचना अधिकारी संबंधित विभागों एवं जोन कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर आदेश पारित होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर आवेदक को नि:शुल्क सूचना उपलब्ध कराएं। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार की चूक होती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी 31 अक्टूबर 2014 के परिपत्र के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

अपर आयुक्त के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आदेश के कई दिनों बाद भी आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे यह प्रश्न उठ रहा है कि जब निगम के प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों का ही पालन नहीं हो रहा है तो सामान्य नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा कैसे होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं होता, तो यह अधिनियम की मूल भावना को प्रभावित करता है।

होर्डिंग व्यवस्था पर पहले से उठते रहे हैं सवाल

शहर में लंबे समय से अवैध होर्डिंग, बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड और राजस्व हानि को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में स्वीकृत और अवैध होर्डिंगों की जानकारी सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो सकता है कि शहर में कितने होर्डिंग वैध अनुमति के साथ संचालित हो रहे हैं, कितनों पर कार्रवाई हुई है और निगम को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसी कारण इस मामले में मांगी गई जानकारी को सार्वजनिक हित से जुड़ा माना जा रहा है।

राज्य सूचना आयोग जाने की तैयारी

चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई इसलिए अब मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच सकता है। आरटीआई के तहत यदि सक्षम अधिकारी के आदेशों के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आयोग संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है।

एमआईसी में होगी चर्चा

"शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे बैनर पोस्टर चिंता जनक है। लगातार इसे लेकर कार्रवाई भी हो रही है। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है। हमारे संज्ञान में मामला आया तो इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में एमआईसी की बैठक में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को रखा जाएगा।

– **सीजू एंथोनी**
एमआईसी सदस्य, राजस्व प्रभारी

उठ रहे हैं कई अहम सवाल

- जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 10 दिन के भीतर सूचना देने का आदेश दिया था, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ?
- क्या संबंधित जोन कार्यालयों ने आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई?
- यदि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?
- आदेश में कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई?
- क्या सूचना को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया या विभागीय समन्वय की कमी इसका कारण है?

इन सवालों के जवाब मिलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह मामला केवल एक आरटीआई आवेदन तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। यदि निगम के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का भी समय पर पालन नहीं होता, तो आम नागरिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठना लाजिमी है।

अपर आयुक्त ने नहीं उठाया फोन

"इस पूरे मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी व अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे का पक्ष जानने श्रीकंचनपथ के संवाददाता ने उनसे संपर्क किया। लगातार कॉल करने के बाद भी उनकी ओर से कॉल रिसीव नहीं किया गया। यहां यह बताना भी जरूरी है कि इन्हीं के द्वारा सभी जोन आयुक्तों को निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद भी इनके निर्देश का पालन नहीं किया गया।

बस्तर के जंगलों की हाई-टेक निगरानी

रात में भी वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध कटाई और शिकार पर रखी जाएगी नजर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बस्तर वन मंडल में घने जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाई-टेक निगरानी शुरू की गई है। इससे रात के अंधेरे में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, अवैध कटाई व शिकार पर रोक लग रही है, और अज्ञात वन्यजीवों के पगचिन्ह मिलने पर उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी गर्मी (बॉडी हीट) के आधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेते हैं। हाल ही में माचकोट और बिलोरी के जंगलों में किसी अज्ञात खूंखार वन्यप्राणी के पंजे के निशान मिलने के बाद वन विभाग ने सुरक्षा और तलाश के लिए इन ड्रोनों को तैनात किया है। जंगलों में लकड़ी की तस्करी, अवैध कटाई और शिकार जैसी असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिल रही है।

वन मंत्री केदार कश्यप की मंशानुरूप बस्तर के घने जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। बस्तर वन मंडल में कांकेर वन मंडल के सहयोग से थर्मल इमेजिंग ड्रोन के माध्यम से जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से रात्रिकालीन निगरानी की जा रही है। जल्द ही बस्तर वन मंडल को भी

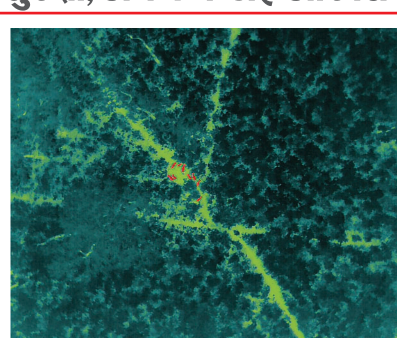

अपना थर्मल ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा।

घने जंगलों और अंधेरे में भी वन्यजीवों तथा मानव गतिविधियों की मिलेगी जानकारी

थर्मल ड्रोन शरीर की गर्मी (हीट सिग्नेचर) के आधार पर घने जंगलों और अंधेरे में भी वन्यजीवों तथा मानव गतिविधियों का पता लगा सकता है। इससे भालू, तेंदुआ, हाथी सहित अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल रही है। साथ ही अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने मिलेगी मदद

वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी कर रहा है। यदि जंगल से लगे गांवों में हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी की सूचना मिलती है, तो थर्मल ड्रोन से उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर ग्रामीणों को समय पर सतर्क किया जाता है, जिससे जन-धन की हानि की आशंका कम होती है। रात्रि के समय संदिग्ध गतिविधियों की पहचान होने पर ड्रोन से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। इससे वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और वनकर्मियों की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई हैं।

रात्रिकालीन गश्त अधिक प्रभावी होगा तथा बस्तर की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में मिल रही सहायता

डीएफओ बस्तर उत्तम गुप्ता ने बताया कि वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार आधुनिक तकनीक से वन संरक्षण को नई मजबूती मिली है। वर्तमान में कांकेर वन मंडल के सहयोग से थर्मल ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और शीघ्र ही बस्तर वन मंडल को भी अपना थर्मल ड्रोन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे रात्रिकालीन गश्त अधिक प्रभावी हुई है तथा बस्तर की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है।

आग का तांडव: बार सहित 4 दुकानें और कई गाड़ियां जलकर खाक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित ऑक्टोपस बार के पास देर रात भीषण आग लग गई। इससे बार समेत चार दुकानें जलकर राख हो गईं। आग पर काबू पाने के लिये फायर बिग्रेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची।

बताया जाता है कि सबसे पहले आग हार्डवेयर की दुकान में लगी, फिर उसकी लपटें बार सहित आस-पास की चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर धीरे-धीरे उसके सामने खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। टीम बचाव और राहत कार्य में जुटी रही। सुबह तक आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया गया था। अब भी चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है।

मामले में तेलीबांधा टीआई अजय झा ने बताया कि आग हार्डवेयर दुकान से लगी थी। आगे कैसे लगी, ये अभी मालूम नहीं चल सका है। आग इतनी भीषण लगी थी कि तेज बारिश के बाद भी उस पर काबू पाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इससे ऑक्टोपस बार समेत तीन दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल, आग लगने की वजह नहीं पता चल सकी है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया जाता है कि देर रात डेढ़-दो बजे के करीब आग लगी। इस दौरान रायपुर में बारिश हो रही थी पर आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को पसीने बहाने पड़े। दमकल की 13 गाड़ियां लगातार पानी की बौछारें बरसाती रहीं। आग पर काबू पाने में लगी रहीं। घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। हालांकि सुबह तक धुआं उठते हुए दिखाई दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी भीषण थी कि लोगों को अपना सामान निकालने तक का समय नहीं मिला। बार और होटल को भी आग से काफी नुकसान पहुंचा है। आग से प्रभावित दुकानदार बॉबी तोलानी ने बताया कि देर रात उन्हें आग लगने की सूचना मिली। इस पर वो बिना देरी किए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। इस वजह से सामान बचाने के लिये उन्हें मौका तक नहीं मिल सका। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस दौरान होटल में ठहरे लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मामले में रायपुर जिला प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। आग कैसे लगी? इसे लेकर पुलिस और दमकल की टीम मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, आग बुझा ली गई है। फिर भी टीम मौके पर मौजूद है। कुलिंग का काम चल रहा है।

संपादकीय

इथेनॉल पर सवाल

बदलाव के लिए प्रामाणिक डेटा ज़रूरी

पेट्रोलियम पदार्थों के विदेशों से आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता हमेशा गंभीर चिंता का विषय रही है। खासकर, हालिया पश्चिम एशिया संकट के दौरान हॉर्मूज खाड़ी में कच्चे तेल व गैस टैंकरों की आवाजाही पर रोक ने स्थिति की गंभीरता को दर्शाया। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये इसमें इथेनॉल मिलाने का विकल्प चुना। लेकिन आज इसके साइड इफेक्ट को लेकर देश में चिंता बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि इससे वाहनों की माइलेज कम हुई है। कुछ की आशंका है कि गाड़ियों के रखरखाव की लागत बढ़ी है। दरअसल, इसकी वजह इथेनॉल के उपयोग को लेकर किसी प्रामाणिक अध्ययन का सामने न आना भी रहा है। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि उसने अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं किया है, जिससे पता चल सके कि देश में कितने वाहन ई-20 यानी अस्सी प्रतिशत पेट्रोल व बीस प्रतिशत इथेनॉल के अनुकूल हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे यह बात साबित होती है कि देश के हरित ऊर्जा के लक्ष्यों और जमीनी स्तर की तैयारियों के बीच कितना अंतर है। ऐसे में वाहनों की प्रामाणिक गिनती या सर्वे के बिना देशव्यापी बदलाव के सफल होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? निस्संदेह ई-20 को बढ़ावा देने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटाना और भारत की बायोफ्यूल वाली अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना है। वहीं सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों और फील्ड ट्रायल में यह वैकल्पिक ईंधन निर्धारित मानकों के तहत प्रयोग के लिये सुरक्षित पाया गया है। निस्संदेह, नियंत्रित स्थिति में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन जब लाखों वाहन चालकों को प्रभावित करने वाली किसी नीति का क्रियान्वयन किया जाता है तो जनता का विश्वास हासिल करने के लिये प्रामाणिक डेटा की भी जरूरत होती है।

“ दरअसल, इसकी वजह इथेनॉल के उपयोग को लेकर किसी प्रामाणिक अध्ययन का सामने न आना भी रहा है। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि उसने अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं किया है, जिससे पता चल सके कि देश में कितने वाहन ई-20 यानी अस्सी प्रतिशत पेट्रोल व बीस प्रतिशत इथेनॉल के अनुकूल हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे यह बात साबित होती है कि देश के हरित ऊर्जा के लक्ष्यों और जमीनी स्तर की तैयारियों के बीच कितना अंतर है। ऐसे में वाहनों की प्रामाणिक गिनती या सर्वे के बिना देशव्यापी बदलाव के सफल होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? निस्संदेह ई-20 को बढ़ावा देने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है।

बहरहाल, संसद में सरकार की स्वीकारोक्ति से इस नीति को लेकर विरोधाभास तो उजागर होता ही है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों से बीस करोड़ दुपहिया वाहनों और तीन करोड़ से ज्यादा पेट्रोल से चलने वाली कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी दलील है कि इसके बावजूद कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि, सरकार की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि जिन वाहनों को लेकर वह दावा कर रही है, उसमें कितने वाहन ई-20 के लिये डिजाइन या प्रमाणित थे। ऐसी किसी बुनियादी जानकारी के बिना, सुरक्षा और परफॉर्मेंस के बारे में दिए गए भरोसे के शब्द शायद ही लोगों को विश्वास दिला पाएं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उनके लिये लाभकारी है। हाल के दिनों में पूरे देश से इथेनॉल के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। मुद्दा सार्वजनिक विमर्श का विषय बना हुआ है। कुछ संगठन आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के विरोध, विपक्ष की इस मामले में पारदर्शिता की मांग और 'ई-20 जनता पार्टी' जैसे व्यंग्यात्मक ऑनलाइन कैंपेन लोगों की इस बाबत बढ़ती चिंता को ही दर्शाता है। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे को समय रहते गंभीरता से लेने की जरूरत है। सही मायने में ग्राहकों को वारंटी सुरक्षा, लंबे समय तक रखरखाव के खर्च, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की माइलेज और इंजन व अन्य उपकरण खराब होने की जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी ही चाहिए। इस बाबत सरकार द्वारा दी गई केवल सफाई भरोसे का आधार नहीं बन सकती। इसके लिये प्रामाणिक तथ्यों की भी जरूरत है। वहीं सरकार के इस बाबत संकेत से कि ज्यादा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जा रही है,से यह पता जरूर चलता कि ई-20 आखिरी पड़ाव न हो। निश्चित रूप से इस तरह के किसी कदम के लिये जनता को विश्वास में लेने और डेटा आधारित पॉलिसी बनाने की जरूरत है। किसी नीति के लाभदायक होने के साथ ही जरूरी है लोगों को यह लगना कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

इसरो के लिए प्रतिभाओं को थामे रखने की चुनौती

दिनेश सी शर्मा

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के उभार के बीच स्पेस एजेंसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। इनमें कई वैज्ञानिक देश के अहम अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स से जुड़े थे। बेहतर वेतन, ग्रोथ व प्रोजेक्ट के चलते इंजीनियर्स ने कंपनियों का रुख किया। अभी इस पलायन पर रोक लगी है लेकिन बेहतर होगा कि इसरो वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाए।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अच्छी और बुरी, दोनों वजहों से सुर्खियों में है। अच्छी खबर यह है कि भारत की एक निजी कंपनी, 'स्काईरूट' ने पहला 'एंड-टू-एंड' (आरंभ से अंत तक) निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरा कर दिखाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के दो पूर्व इंजीनियरों द्वारा शुरू की गई इस कंपनी ने अपने रॉकेट, विक्रम-1 की प्रथम उड़ान सफल बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी को उम्मीद है कि वह अगले साल इस रॉकेट का उन्नत प्रारूप विक्रम-2 उड़ा पाएगी। इसका मकसद 'लो अर्थ ऑर्बिट' (पृथ्वी की निचली कक्षा) में सैटेलाइट स्थापित करने के अरबों डॉलर के बाज़ार में उतरना है।

बुरी खबर इसरो के बारे में है, जहां से कई बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक, यू.आर. राव स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और नेशनल स्पेस एजेंसी की अन्य अहम इकाइयों में काम करने वाले दर्जनों वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली। इनमें से कई वैज्ञानिक भारत की अग्रणी अंतरिक्ष परियोजनाओं, जैसे कि गगनयान मिशन (इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन), नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों पर काम कर रहे थे।

हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अंतरिक्ष विभाग को इस पलायन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करना पड़ा है। उसने निर्देश दिया है कि अहम मिशनों से जुड़े लोगों को परियोजना पूरी होने तक इसरो छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरसरी तौर पर देखें तो भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का प्रक्षेपण और इसरो से प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) एक-दूसरे से अलग लग सकते हैं। लेकिन असल में, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो की इकाइयों में इस्तीफों की बाढ़ का सबसे परोक्ष कारण पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियों का उभरना है। यह सरकार के उस फैसले का सीधा नतीजा है, जिसमें निजी कंपनियों को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने तथा उनका प्रक्षेपण करने की इजाज़त दी गई थी। इस नीति के आने से पहले भारतीय भूमि से रॉकेट छोड़ने के काम पर केवल इसरो का एकाधिकार था। सरकार ने न सिर्फ़ निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाज़े खोल दिए, बल्कि इसरो को यह भी निर्देश दिया कि वह कंपनियों को अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने दे। इन सबने एक ऐसी स्थिति बना दी, जिसमें निजी कंपनियों ने इसरो की इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को आकर्षक वेतन, सुविधाओं और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं से लुभाकर अपनी ओर खींच लिया।

सरकारी संस्थानों से निजी क्षेत्र में प्रतिभा का इस प्रकार का पलायन इसरो के लिए कोई नई बात नहीं है और न ही यह केवल अंतरिक्ष क्षेत्र तक ही सीमित है। अमेरिका का नामी निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, नासा द्वारा तैयार और प्रशिक्षित किए गए लोगों (मानव संसाधन) के दम पर ही खड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आरंभिक दौर में निजी कंपनियों ने अपनी अनुसंधान एवं विकास टीमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़इंडिया लिमिटेड और कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों से लोगों को लाकर तैयार की थीं। ऐसा ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जैसी महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों के मामले में भी हुआ।

रक्षा एवं एयरोस्पेस उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं में भी इसरो जैसी ही स्थिति बनी हुई है। हमारी वैज्ञानिक एजेंसियों, चाहे वे इसरो हों या डीआरडीओ, को आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसके कारणों पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।

मार्च 2026 में, अंतरिक्ष विभाग की समीक्षा करने वाली एक संसदीय समिति को बताया गया था कि इसरो की अलग-अलग इकाइयों में कुल मंजूर 18,000 पदों में लगभग 2,800 से अधिक पद खाली पड़े हैं। नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने वाले संस्थान, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भी लगभग 500 पद खाली हैं। एक ओर निजी कंपनियां अनुभवी वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींच रही हैं, तो दूसरी तरफ़ इसरो की परियोजनाओं को सरकार से पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही है।

उदाहरण के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी थी। इसके तहत रॉकेट विकसित करने हेतु, सुविधा शुरू करने से लेकर प्रक्षेपण तक, 96 महीनों की समय-सीमा तय की गई। मंज़ूरी की तारीख से 84 महीनों के भीतर पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मंज़ूरी मिलने के बाद भी कई माह तक यह परियोजना कागज़ों पर ही रही, क्योंकि 2024-25 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संशोधित अनुमान के तहत 3 करोड़ रुपये का एक प्रतीकात्मक आवंटन किया गया, जिसमें से इसरो 85 लाख रुपये ही खर्च पाया। 2025-26 के बजट में शुरू में 158 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे भी घटाकर 39.76 करोड़ रुपये कर दिया। इस धन में से इसरो ने 31 जनवरी, 2026 तक केवल 7.93 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए। फंडिंग में देरी और स्टाफ की कमी ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तय समय-सीमा पर बुरा असर डाल सकती है।

फंड का पूरा उपयोग न होना, बजटीय आवंटन में कटौती, खाली पदों को भरने में देरी और निजी क्षेत्र की आमद-ये सभी चीज़ें इसरो में एक गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं। तिस पर, प्रमुख रॉकेट परियोजना यानी पीएसएलवी से जुड़ी कई नाकामियां मिली हैं और गगनयान जैसे मुश्किल मिशनों में भी भारी देरी हुई। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण तथा बढ़ती अफ़सरशाही एवं सियासी दखलंदाज़ी भी एक बड़े मिशन-उन्मुख वैज्ञानिक संस्थान के कामकाज के लिए अच्छे संकेत नहीं। नतीजन, वैज्ञानिकों का मनोबल गिरा है और वे आमतौर पर निराश महसूस कर रहे हैं।

यह सब चीज़ें राजनीतिक नेतृत्व, नीति-निर्माताओं और अंतरिक्ष एजेंसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वैज्ञानिकों से इस्तीफा न देने को कहना और इन्हें स्वीकार न करने का आदेश जारी कर देना ही काफी नहीं। केंद्र सरकार, जिसने निजी क्षेत्र के प्रवेश पर ज़ोर दिया, और इसरो, जिसने इसकी राह आसान की, उन्हें इस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर पड़ने वाले इस प्रकार के असर का अंदाज़ा पहले से होना चाहिए था और इससे निबटने को पहले से ही कदम उठाने चाहिए थे। इसरो के नेतृत्व को वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए, जो मिशन की नाकामियों और देरी से प्रभावित हुआ है।

दीर्घकालीन नीति में एजेंसी को नए और अनोखे तरीकों के बारे में सोचना होगा,जैसे कि वैज्ञानिकों को इसरो में अपने कार्य के दौरान ही कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने की इजाज़त देना, गैर-अति महत्वपूर्ण या कम अहम क्षेत्रों में अपनी कंपनियां शुरू करने की अनुमति देना, साथ ही वेतन ढांचा, तरक्की की नीतियों तथा प्रोत्साहनों में बदलाव करना।

अपनी ओर से सरकार को वैज्ञानिक संस्थानों की स्वायत्तता बहाल करनी चाहिए और राजनीतिक फायदे के लिए इनका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। अंतरिक्ष बाज़ार दुनिया भर में बढ़ रहा है और इस संभावना को तलाशने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी कंपनियों, दोनों के लिए काफी गुंजाइश है। 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को आसानी से 'ब्रेन सर्कुलेशन' (प्रतिभा आदान-प्रदान) में बदला जा सकता है।

लेखक विज्ञान विषयों के विशेषज्ञ हैं।

हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के जनक: बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग

शिक्षाविद - डॉ देवेन्द्र नाथ शर्मा

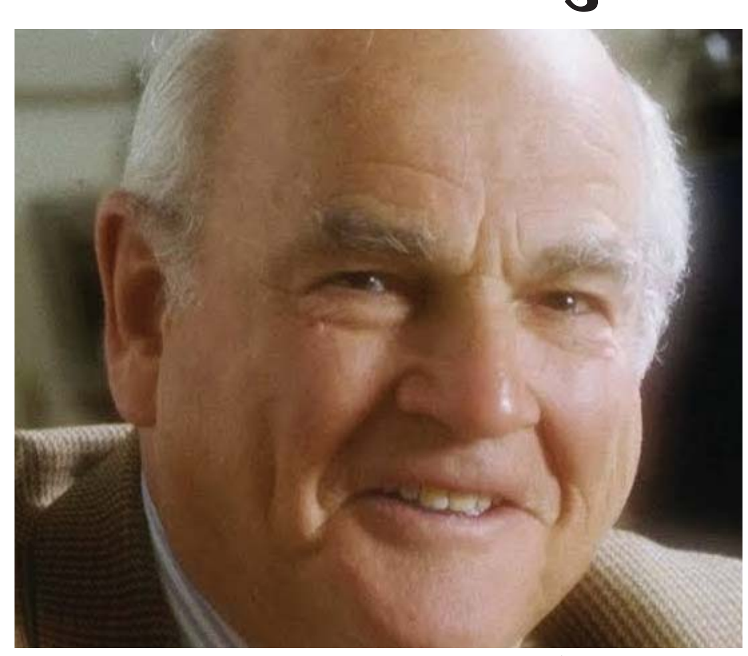

बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग बीसवीं शताब्दी के उन महान चिकित्सकों, आनुवंशिकीविदों और जैव-चिकित्सा वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनकी खोज ने मानवता को एक जानलेवा संक्रमण से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने हेपेटाइटिस बी के कारण की पहचान की और उसके विरुद्ध प्रभावी टीके के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई।

एड्स की तरह घातक इस रोग की रोकथाम के लिए लगभग शत-प्रतिशत सुरक्षा देने वाली वैक्सीन का मार्ग प्रशस्त करने वाले वैज्ञानिक के रूप में उनका नाम चिकित्सा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनकी खोजों ने न केवल रोग की पहचान की, बल्कि उसके प्रभावी नियंत्रण का द्वार भी खोला। वैज्ञानिक जिज्ञासा, मानव सेवा और अथक अनुसंधान का यह उत्कृष्ट उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

यहूदी मूल के ब्लमबर्ग का जन्म 28 जुलाई 1925 को न्यूयॉर्क (अमेरिका) में हुआ। यूनियन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से चिकित्सा में एम.डी. और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से जैव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में भी उन्होंने सेवा दी।

1965 में विभिन्न जनसमूहों के रक्त नमूनों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक विशेष प्रोटीन की पहचान की, जिसे बाद में 'ऑस्ट्रेलिया एंटीजन' कहा गया। आगे चलकर यह हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) का सतही एंटीजन (HBsAg) सिद्ध हुआ। उनके अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है, जो रक्त और शरीर के अन्य द्रवों के माध्यम से फैलता है।

इस खोज के आधार पर रक्तदान से पहले हेपेटाइटिस बी की जाँच संभव हुई, जिससे संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटनाओं में भारी कमी आई। यही खोज विश्व की पहली प्रभावी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के विकास का आधार बनी। आज यह टीका अनेक देशों के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

1976 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उन्हें डेनियल कार्लेटन गाइड्यूसेक के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यह सम्मान संक्रामक रोगों की उत्पत्ति और नियंत्रण संबंधी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया।

इसके अतिरिक्त वे नासा के एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्रथम निदेशक भी रहे और मानव स्वास्थ्य, आनुवंशिकी तथा अंतरिक्ष जीव विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। 5 अप्रैल 2011 को उनका निधन हो गया। हेपेटाइटिस बी यकृत (लीवर) का संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह तीव्र (अल्पकालिक और गंभीर) या दीर्घकालिक हो सकता है। दीर्घकालिक संक्रमण सिरोसिस और लीवर कैंसर का उच्च जोखिम पैदा करता है। रोग संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों—जैसे रक्त, योनि द्रव, वीर्य या लार—के संपर्क से फैलता है तथा माता से नवजात शिशु में भी संचारित हो सकता है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार भारत में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं द्य इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है; एंटीवायरल दवाओं से नियंत्रण का प्रयास किया जाता है।

परंतु वैक्सीन से इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। यह टीका आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और कुछ सप्ताह बाद बूस्टर खुराक दी जाती है। यह वायरस से लगभग 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करता है।

बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग का जीवन हमें याद दिलाता है कि एक वैज्ञानिक की लगन और मानवता के प्रति समर्पण कितने जीवन बचा सकता है। उनकी विरासत आज भी विश्व भर में टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवित है।

विज्ञान-तकनीक के सहारे सुरक्षित बाघों की दुनिया

डॉ. शुशिल द्विवेदी

मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां बाघों की गतिविधियों का विश्लेषण कर यह बताने में सक्षम हैं कि किसी क्षेत्र में मानव-बाघ संघर्ष की आशंका कितनी है, किस दिशा में बाघों का आवागमन बढ़ रहा है और किन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है।

हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन बाघ संरक्षण के साथ प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन के गहरे संबंध का स्मरण भी कराता है। बाघ केवल जंगल का राजा नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रहरी है। जहां बाघ सुरक्षित हैं, वहां जंगल जीवित हैं; जहां जंगल सुरक्षित हैं, वहां नदियां बहती हैं, भूजल संरक्षित रहता है और जैव विविधता फलती-फूलती है। तभी कहा जाता है, 'टाइगर रहेगा तो इंसान भी रहेगा।' एक समय अवैध शिकार, जंगलों की सिकुड़न, अनियंत्रित शहरीकरण, खनन, सड़क-रेल परियोजनाओं तथा बढ़ते मानव-बाघ संघर्ष ने बाघों की संख्या को चिंताजनक स्तर तक पहुंचा दिया था। वर्ष 2006 में देश में केवल 1,411 बाघ शेष बचे थे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों, वन विभाग, वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों तथा विभिन्न संस्थाओं ने समन्वित प्रयास शुरू किए। आज विश्व के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में हैं। यह उपलब्धि केवल संरक्षण नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान, तकनीक और जनभागीदारी के सफल प्रयोग का प्रमाण है।

पिछले एक दशक में विज्ञान और तकनीक ने बाघ संरक्षण की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां वनकर्मियों को कई दिनों तक जंगलों में पैदल घूमकर पगचिह्नों के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता था, वहीं आज कैमरा ट्रैप, एआई, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, जीपीएस कॉलर और डिजिटल डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों ने संरक्षण कार्य को अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है। कैमरा ट्रैप आज बाघ संरक्षण का सबसे विश्वसनीय उपकरण माना जाता है। ये विशेष कैमरे मोशन सेंसर की सहायता से किसी भी वन्यजीव की तस्वीर या वीडियो स्वत: रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाघों की पहचान उनके शरीर पर बनी धारियों से होती है और प्रत्येक बाघ की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह अलग होती हैं। कैमरा ट्रैप से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक प्रत्येक बाघ की अलग पहचान कर उसकी गतिविधियों, क्षेत्र, प्रजनन और संख्या का सटीक आकलन कर पाते हैं। यही कारण है कि भारतीय बाघ गणना आज दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक वन्यजीव निगरानी परियोजनाओं में गिनी जाती है।

दरअसल, कैमरा ट्रैप से हर वर्ष लाखों तस्वीरें और वीडियो प्राप्त होते हैं। पहले इनका विश्लेषण करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब एआई आधारित सॉफ्टवेयर कुछ ही घंटों में यह पहचान लेते हैं कि तस्वीर में बाघ है, तेंदुआ है, हाथी है या कोई अन्य वन्यजीव। इतना ही नहीं, एआई बाघों की धारियों का विश्लेषण करके उनकी व्यक्तिगत पहचान भी सुनिश्चित कर सकता है। इससे गणना अधिक सटीक हुई है और समय की उल्लेखनीय बचत हुई है।

मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां बाघों की गतिविधियों का विश्लेषण कर यह बताने में सक्षम हैं कि किसी क्षेत्र में मानव-बाघ संघर्ष की आशंका कितनी है, किस दिशा में बाघों का आवागमन बढ़ रहा है और किन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार एआई भविष्य की संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। घने जंगलों में ड्रोन तकनीक उपयोगी सिद्ध हुई है। आधुनिक ड्रोन उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे वे रात के समय भी जंगलों की निगरानी कर सकते हैं। इनके माध्यम से अवैध शिकार करने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और जंगलों में आग लगने की प्रारंभिक जानकारी मिल सकती है। इससे दुर्गम क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है।

वहीं, अंतरिक्ष से प्राप्त चित्रों के आधार पर जंगलों में हो रहे परिवर्तनों की लगातार निगरानी की जाती है। यदि कहीं अवैध कटाई, अतिक्रमण या वन क्षेत्र में कमी दिखाई देती है तो संबंधित एजेंसियां तत्काल कार्रवाई कर सकती हैं। इससे बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने में सहायता मिल रही है।

आज अधिकांश टाइगर रिजर्व में वनकर्मी जीपीएस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से गश्त करते हैं। उनकी गतिविधियां डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती हैं। किस क्षेत्र में कितनी गश्त हुई, कहां वन्यजीव दिखाई दिए, कहां संदिग्ध गतिविधियां मिलीं—सारी जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाती है। डिजिटल डेटा के विश्लेषण से सुरक्षा रणनीति तैयार की जाती है। कुछ बाघों को विशेष जीपीएस रेडियो कॉलर भी पहनाए जाते हैं। इनके माध्यम से वैज्ञानिक उनकी लोकेशन, आवागमन, प्रजनन क्षेत्र और भोजन की तलाश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई बाघ मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहा हो तो वन विभाग पहले से सतर्क होकर जरूरी कदम उठा सकता है। भोजन या नए क्षेत्र की तलाश में कभी-कभी बाघ गांवों तक पहुंच जाते हैं, जिससे मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। अब एआई आधारित चेतावनी प्रणाली से संबंधित गांवों और वन अधिकारियों को तुरंत सूचना भेजी जाती है। इससे ग्रामीण सतर्क हो जाते हैं।

बाघों के सामने आज सबसे बड़ा खतरा अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी है। अब एआई संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण करता है, ड्रोन जंगलों की निगरानी करते हैं और कैमरा ट्रैप संदिग्ध गतिविधियों की तस्वीरें रिकॉर्ड करते हैं। वहीं, डिजिटल नेटवर्किंग से वन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से दुनिया में संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है।

लेखक विज्ञान और पर्यावरण मामलों के जानकार हैं।

ITR फाइल 500/-

Whatsapp पर बनवाएँ

Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस

हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।

www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ

भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें

Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

जिले में 7 से 15 अगस्त तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

दुर्ग। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण राज्य में चार चरणों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिले में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय चरण के अंतर्गत 07 से 15 अगस्त 2026 तक (हर घर तिरंगा अभियान के साथ) विभिन्न देशभक्तिपूर्ण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिले के सर्व विभाग प्रमुखों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों के तहत, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत मुख्यालयों सहित सभी स्कूल और कॉलेजों में ध्वजारोहण के पश्चात व्यापक स्तर पर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन किया जाएगा। अभियान की अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, मशाल रैली, देशभक्ति गीत, विचार गोष्ठी एवं छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।

शिक्षकों को कर्तव्य प्रमाण पत्र व अर्जित अवकाश प्रदान संबंधी आदेश निरस्त

दुर्ग। कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक कर्तव्य प्रमाण पत्र (ड्यूटी सर्टिफिकेट) जारी करने तथा अर्जित अवकाश प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा सौंपे गए दायित्वों के सफल निर्वहन का उल्लेख करते हुए कार्यरत शिक्षकों को कर्तव्य प्रमाण-पत्र जारी करने एवं अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में जारी पूर्व आदेश को प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से निरस्त करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस विषय में शासन से आगामी दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही आगे की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिले में अब तक 423.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

दुर्ग। जिले में 1 जून 2026 से 28 जुलाई 2026 तक 423.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 517.5 मिमी तहसील पाटन में तथा न्यूनतम 286.5 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 472.4 मिमी, तहसील बोरी में 515.1 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 405.9 मिमी और तहसील अहिवारा में 343.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

एक दिन में मिला विवाह प्रमाण पत्र, सेवा सेतु ने आसान बनाया जरूरी दस्तावेज प्राप्त करना

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शासन की डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित 'सेवा सेतु जनता के द्वार, डिजिटल सरकार' अभियान आम नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रहा है। अब लोगों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

दुर्ग जिले के ग्राम सांकरा अहिवारा निवासी प्रीतम साहू ने अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए सेवा सेतु केन्द्र, ग्राम पंचायत मलपुरी कला में आवेदन किया।

सेवा सेतु केन्द्र की त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया के चलते उन्हें एक ही दिन में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रीतम साहू ने बताया कि पहले इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय भी अधिक लगता था। लेकिन सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से उनका कार्य बेहद सरल और तेज़ी से पूरा हुआ। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार एवं पैन कार्ड सेवाएं, राशन कार्ड सेवाएं, ऑनलाइन फॉर्म तथा सीएससी से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों को समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है तथा शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।

ई-ऑफिस मूल्यांकन उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विभाग होंगे पुरस्कृत- कलेक्टर सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में कार्यदक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने शासन द्वारा ई-ऑफिस प्रक्रिया लागू की गई है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन पश्चात् उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को मंत्रालय स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है। यह व्यवस्था अब जिलों में भी अगस्त माह से ई-फाईलों की मॉनिटरिंग के साथ प्रारंभ की जाएगी और मूल्यांकन पश्चात् जिला स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी पुरस्कृत होंगे।

कलेक्टर सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में उक्त बातें कही। उन्होंने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में विभागवार गहन समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ई-ऑफिस में फाईलों को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखे तथा आवश्यकतानुसार क्लोज एवं पार्क विकल्प का उपयोग कर उनका नियमित प्रबंधन सुनिश्चित करें। जिन फाईलों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिन पर आगे कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है, उन्हें क्लोज करें। इसी प्रकार जिन फाइलों पर वर्तमान में कार्य संभव नहीं है अथवा किसी सूचना, अनुमोदन या अन्य कार्यवाही की प्रतिक्षा है, उन्हें पार्क करें। आवश्यकता के अनुसार 15 दिन या उपर्युक्त अवधि के लिए पार्क टिल डेट (पार्क होने तक की तिथि) निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर पार्क की गई फाईल को अनपार्क तथा क्लोज की गई फ ाईल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रि-ओपन किया जा सकता है। कलेक्टर सिंह ने ई-ऑफिस की उक्त प्रक्रिया से अधिकारियों को अधीनस्थ विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को भली-भांति समझाने के निर्देश दिए। साथ ही ई-ऑफिस से संबंधित फाईलें 31 जुलाई 2026 तक क्लोज कर लेने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की आधार बेस अटेंडेंस पर जोर देते हुए सभी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा आगामी माह से वेतन भुगतान आधार बेस अटेंडेंस पर निर्धारित करने का विचार किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पीजी पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, ई-समाधान, मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायत के प्रकरणों के निराकरण गंभीरतापूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण 50 दिवस से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान ग्राम-पंचायतों में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारें के बढ़ते लंबित प्रकरणों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने संबंधित जनपद सीईओ को प्रकरणों का परीक्षण कर निराकृत कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने आगामी दिनों में नगर निगम रिसाली, भिलाई एवं भिलाई-03 चरौदा तथा नगर पालिका जामुल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सांख्यिकी अधिकारी को वार्ड आरक्षण के संबंध में आवश्यक जानकारियां संबंधित नगरीय निकायों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को संबंधित क्षेत्र के किसानों को मुआवजे के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने सीएमएचओ से आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन योजना के कार्यों की जानकारी ली।

भिलाई शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने निगम की नई पहल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत शहर के प्रमुख एवं व्यस्त चौक-चौराहों पर लेफ्ट फ्री व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि वाहन चालकों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके और यातायात का दबाव कम किया जा सके।

नगर निगम द्वारा चंद्रा मौर्या चौक, घड़ी चौक, नेहरू नगर चौक, सूर्या मॉल चौक सहित अन्य ऐसे प्रमुख स्थलों को चिन्हित कर स्वीकृत किया गया है, जहां दिनभर वाहनों का अधिक आवागमन एवं यातायात का दबाव रहता है। इन स्थानों पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लेफ्ट फ्री हेतु कार्य की जा रही है, जिससे वाहन चालकों को बाएं मुड़ने के लिए अनावश्यक रूप से सिग्नल या चौराहे पर रुकना न पड़े और यातायात का प्रवाह लगातार बना रहे। लेफ्ट फ्री व्यवस्था से चौराहों पर वाहनों के अनावश्यक रुकने एवं जाम की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही वाहनों के बार-बार रुकने और चालू होने से होने वाली अतिरिक्त ईंधन खपत में भी कमी आएगी। यातायात के सुचारू संचालन से वाहन चालकों का समय बचने के साथ ही चौराहों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने में भी सहायता मिलेगी। लेफ्ट फ्री निर्माण से वायु गुणवत्ता में सुधार कर प्रदूषण में कमी आएगी ।

नगर निगम भिलाई का उद्देश्य शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं सुगम बनाना है। प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट फ्री व्यवस्था विकसित होने से आम नागरिकों को आवागमन में राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

इस्पात गलन शाला 3 में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी इस्पात गलन शाला-3 के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इस्पात गलन शाला-3 में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभिन्न एजेंसियों के 37 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक (इस्पात गलन शाला-3) त्रिभुवन बैठा थे।

कार्यशाला में सुशील कामड़े, सहायक महाप्रबंधक प्रकाश आत्मपूज्य, सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन), नीरज कुमार दुबे, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रचालन), उमेश कोरे, उप प्रबंधक (क्रेन मेंटेनेन्स-मेकेनिकल), तुषार रविन्द्र अगलावे, उप प्रबंधक (प्रचालन), सुश्री सरस्वती, सहायक प्रबंधक (प्रचालन) सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक (इस्पात गलन शाला3), त्रिभुवन बैठा ने राजभाषा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी कार्मिकों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही इस्पात गलन शालाङ्क3 ने निष्पादन के समग्र क्षेत्रों सहित हिंदी में कार्यालयीन कार्यों की दिशा में भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि विभाग को 'निदेशक प्रभारी राजभाषा वैजयंती पुरस्कार' मिला है। उत्कृष्टता की इस परंपरा को निरंतर जारी रखने विभाग पूर्णतः संकल्पित है। महाप्रबंधक एवं विभागीय राजभाषा समन्वय अधिकारी उमाशंकर परगनिहा ने राजभाषा के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक द्वारा जारी जाँच बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित चेक प्वाइंट्स के अनुपालन तथा राजभाषा कार्यों की सतत निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनाने के लिए हिंदी मुहावरों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार तुषार रविन्द्र अगलावे, उप प्रबंधक सीमा शर्मा, इंजीनियरिंग एसोसिएट को प्रदान किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 153वीं तिमाही समीक्षा बैठक संपन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 153वीं तिमाही समीक्षा बैठक दिनांक 28 जुलाई 2026 को कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई इस्पात संयंत्र, पवन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में महाप्रबंधक प्रभारी अमूल्य प्रियदर्शी, महाप्रबंधक सौमिक डे, उप महाप्रबंधक राघवेन्द्र कुमार गर्ग तथा ऑनलाइन माध्यम से समस्त कार्यपालक निदेशकगण, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारीगण, मुख्य महाप्रबंधकगण, संयंत्र के सभी विभाग प्रमुखगण व समस्त विभागीय हिंदी समन्वय अधिकारीगण उपस्थित थे। सर्वप्रथम महाप्रबंधक प्रभारी अमूल्य प्रियदर्शी ने पुस्तक भेंट कर कार्यपालक निदेशक पवन कुमार का स्वागत किया। श्री राघवेन्द्र कुमार गर्ग ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए सितंबर माह में राजभाषा पखवाड़ा के आयोजन की जानकारी दी व कहा कि प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी में कार्यालयीन कामकाज को प्रोत्साहन की दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विभाग प्रमुखगण से राजभाषा पखवाड़ा को सफल बनाने का निवेदन किया।

पवन कुमार ने कहा कि हिंदी में कार्य करने में प्रत्येक कार्मिक की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। आगामी दिनों में भिलाई इस्पात संयंत्र की पत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग की पत्रिका 'महानदी' का प्रकाशन किया जाना है, साथ ही राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है।

उन्होंने सभी विभागप्रमुखों से इन पत्रिकाओं के लिए अधिकाधिक रचनाएँ प्रेषित करने तथा राजभाषा पखवाड़ा में अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष उल्लेख के साथ उन विभागों से हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत बढाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की बात कही जिन विभागों में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कम है।

भुईंया और ई-कोर्ट पोर्टल पर लंबित मामलों का 30 दिनों में करें निराकरण- कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। विगत रविवार 26 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना, भारतमाला परियोजना, एग्रीस्टैक, भू-आबंटन, नजूल, नक्शा बंटांकन सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

कलेक्टर श्री सिंह ने पट्टाधृति सर्वे की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिन पटवारियों ने सर्वे शुरू नहीं किया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही 29 जुलाई तक सभी वार्डों का सर्वे कार्य पूरा करने तथा ग्राम पंचायत उतई एवं चरोदा नगर निगम के द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन और सीमांकन के समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने भुईंया पोर्टल और ई-कोर्ट पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को 30 दिनों के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सचिवों के माध्यम से करने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया। सीमांकन के समय सीमा से बाहर वाले प्रकरण में लिखित प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षकों के द्वारा लेने के निर्देश दिए गए।

स्वामित्व योजना के तहत 239 ग्रामों में मैप सुधार, अंतिम प्रकाशन और अधिकार अभिलेखों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री, एक्सेम्प्टेड कैटेगरी तथा लंबित 'बकेट क्लेम' पंजीयन शीघ्र पूरा करने को कहा गया। यदि किसी कृषक द्वारा बकेट क्लेम पंजीयन कराने से मना किया जाता है, तो उनसे लिखित में लेकर पंचनामा तैयार करने को कहा है।

कलेक्टर ने भारतमाला परियोजना और रेलवे भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि भुगतान तथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत अवार्ड पारित प्रकरणों में रिकार्ड अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

31 जुलाई तक प्रत्येक ग्रामों का अवार्ड पारित की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है। सहमति आधारित भूमि क्रय, भू-आबंटन, जाति प्रमाण पत्र, प्राकृतिक आपदा सहायता, ई-डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा गारंटी, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल किसान किताब, नजूल प्रकरण, नक्शा बंटांकन और वृक्ष कटाई से संबंधित लंबित आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के नियमित बायोमैट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर एडीएम विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस, अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग महेश सिंह राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी पाटन उत्तम ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी धमधा लवकेश कुमार ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी भिलाई-3 प्रकाश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग शहर प्रफुल्ल गुप्ता, सभी तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।

Since 1972

CROWN-TV®

Choice Of Millions

LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

स्मार्ट मीटर बना उपभोक्ताओं का भरोसेमंद साथी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर योजना प्रभावी साबित हो रही है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली की सटीक रीडिंग के साथ रियल टाइम में खपत की जानकारी मिल रही है। रायगढ़ निवासी मोहन सोनी का कहना है कि वे स्वयं भी अपनी बिजली खपत पर आसानी से नजर रख पा रहे हैं। मोहन सोनी ने बताया कि उनके घर में स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद बिजली की रीडिंग पूरी तरह सटीक मिल रही है। जितनी बिजली की खपत होती है, उसका रिकॉर्ड स्वत: दर्ज हो जाता है, जिससे बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। उन्होंने बताया कि मोर बिजली मोबाइल एप के माध्यम से भी वे कभी भी अपने मोबाइल पर बिजली की खपत और मीटर की रीडिंग देख सकते हैं। इससे बिजली उपयोग पर नियमित निगरानी रखना आसान हो गया है और आवश्यकता के अनुसार बिजली की खपत को नियंत्रित करने में भी सुविधा मिल रही है।

आयुष शिविर बना ग्रामीणों के लिए राहत का माध्यम

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सूरजपुर जिला के ग्राम रघुनाथपुर में ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर तथा वयोमित्र योजना के तहत नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आयुष चिकित्सक डॉ. कीर्ति एवं झूलसिंह कंवर (एमपीडब्ल्यू) ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। विशेष रूप से हड्डी एवं जोड़ों के दर्द, गठिया, मांसपेशियों से संबंधित विकारों तथा वृद्धजनों की सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से योग, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

पीएम राहत योजना से सुकमा में मिला पहला जीवनदान

रायपुर। सड़क हादसों में अक्सर गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) ही जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फैसला करता है। कई बार अस्पताल पहुंचने में देरी या पैसों की तंगी मासूम जिंदगियों को छीन लेती है। इसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पीएम राहत योजना अब सुकमा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिले में भी जमीन पर उतर चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से सुकमा जिले में इस योजना के अंतर्गत पहला सफल कैशलेस इलाज का मामला सामने आया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से जिला अस्पताल सुकमा लाया गया। हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और पीड़ित को बिना किसी कागजी या आर्थिक अड़चन के तुरंत इलाज मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी गई।

शाला प्रवेशोत्सव में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत

पुस्तक एवं साइकिल वितरित कर कहा - मन लगाकर पढ़ें, अपने माता-पिता, विद्यालय और जिले का नाम करें रोशन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा के पीएम श्री सेजस, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बालको में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का माथे पर तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। साथ ही विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं साइकिल वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने माता-पिता, विद्यालय तथा जिले का नाम ऊँचा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और प्रत्येक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के शासकीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बन रहे हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की समस्या का समाधान हुआ है तथा सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से नए विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है और शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।

शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर मंत्री देवांगन ने बच्चों, जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के साथ न्योता भोजन में भी सहभागिता की तथा विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं संस्कारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में पार्षद सत्येंद्र दुबे, एल्डरमैन श्रीमती मंदाकिनी त्रिपाठी, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जे.एन. दुबे, प्राचार्य नीलकंठ राठौर, प्रफुल्ल तिवारी सहित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री साय ने एकलव्य के विद्यार्थियों का बढ़ाया उत्साह

खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनिए - मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एकलव्य संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से नीट-2026 में सफल विद्यार्थियों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर जनजातीय समाज के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर, संसाधन और संकल्प मिलने पर प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आपके विद्यालय का नाम 'एकलव्य' है और भारतीय इतिहास में एकलव्य का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श मानकर कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर साधना और समर्पण के बल पर धनुर्विद्या में असाधारण दक्षता प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उसी प्रकार आप भी अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनिए।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों को संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय; बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय का उल्लेख करते हुए गुरु के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करने और उनसे प्राप्त ज्ञान को समाज के हित में उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देशभर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश में एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जहां जनजातीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य की तरह लक्ष्य साधिए, सफलता निश्चित मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीट जैसी कठिन राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आपके परिश्रम, आपके माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इस अवसर पर सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि डॉक्टर का स्थान समाज में अत्यंत सम्माननीय होता है। भगवान हमें जन्म देते हैं, लेकिन डॉक्टर जीवन की रक्षा करते हैं और लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे केवल कुशल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, सहृदय और विनम्र डॉक्टर भी बनें। उन्होंने कहा कि मरीज के प्रति मधुर व्यवहार और संवेदनशीलता भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार डॉक्टर का अपनापन ही मरीज को मानसिक शक्ति प्रदान करता है। एकलव्य संवाद के दौरान धमतरी जिले से आए छात्र राधेश्याम के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पहले विद्यालयों की संख्या सीमित थी और छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि आज सरकार गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हुआ चंद्रकला का पक्के घर का सपना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का मजबूत माध्यम बन रही है। छत्तीसगढ के बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत पामगल निवासी श्रीमती चंद्रकला इसका प्रेरक उदाहरण हैं। इस योजना की मदद से उनका वर्षों पुराना पक्के घर का सपना साकार हो गया है।

पहले चंद्रकला का परिवार कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। बारिश के दिनों में घर में पानी टपकता था और हर समय दुर्घटना का डर बना रहता था। असुरक्षित मकान के कारण परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें पक्का आवास स्वीकृत हुआ। योजना से मिली वित्तीय सहायता तथा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के सहयोग से समय पर उनके नए घर का निर्माण पूरा हुआ। आज उनका परिवार स्वच्छ, सुरक्षित और मजबूत पक्के मकान में खुशहाल जीवन जी रहा है।

नए घर से परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिला है।

अब बारिश और अन्य मौसम की परेशानियों की चिंता नहीं रहती। परिवार का आत्मविश्वास बढ़ा है और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। श्रीमती चंद्रकला ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और हर पात्र परिवार को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कांकेर जिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज कांकेर जिला प्रवास के दौरान कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने अलबेलापारा स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में आज आयोजित संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने जिला अस्पताल में हाल ही में शुरू किए गए एमआरआई सेवाओं का अवलोकन किया तथा प्रतिदिन आने वाले औसतन मरीजों की जानकारी ली। साथ ही मरीजों के साथ आए उनके परिजनों से भेंट कर जिला अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। इसके उपरांत प्रथम तल में स्थित आईपीडी कक्ष में भर्ती मरीजों से

मुलाकात कर सेहतपुर्सी की जानकारी ली। कांकेर विकासखण्ड के ग्राम बारदेवरी से आई मरीज कलावती प्रधान, ग्राम लेण्डारा की मलेरिया से पीड़ित मरीज श्यामबाई यादव तथा प्रवीण तारम का हालचाल जाना तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके उपरांत वे अलबेलापारा स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे जहां पर उन्होंने चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान शिशु चिकित्सा कक्ष में जाकर भर्ती मरीजों से उनकी सेहत का हालचाल जाना तथा मलेरिया से ग्रसित कक्षा चौथी का मरीज समीर उईके से भेंट की।

विकास का कोई विकल्प नहीं: मंत्री टंक राम वर्मा

टंडवा में वर्षों पुरानी मांग पूरी: 8 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड अंतर्गत ग्राम टंडवा में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कुल 8.32 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान मंत्री वर्मा ने ग्राम टंडवा में 444.55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली देहानपारा से झोपड़ा पारा बैकुंठ सड़क (2.675 किमी) और 387.69 लाख रुपये की लागत वाली टंडवा से बैकुंठ सड़क (2.65 किमी) का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 5 लाख रुपये के साइकिल स्टैंड और 10 लाख रुपये के प्रार्थना शेड का लोकार्पण भी संपन्न हुआ।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वर्षों पुरानी सड़क निर्माण की मांग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी इस मार्ग को स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण काम रुक गया था। अब न केवल सड़क की स्वीकृति मिली, बल्कि बोनस के रूप में दो प्रमुख सड़कों की सौगात मिली है। इस मार्ग के बनने से विद्यार्थियों, कामगारों, दुकानदारों और आम जनता को आवागमन में समय की बचत होगी और बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने पंचायत क्षेत्र के कार्यों का ब्योरा देते हुए बताया कि विगत ढाई वर्षों के कार्यकाल में पंचायत में लगभग 77 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें शेड निर्माण, महतारी सदन, पीडीएस भवन, उद्यान विकास, शौचालय, साइकिल स्टैंड और स्मार्ट क्लास जैसे जनहितकारी कार्य शामिल हैं।

छात्र जीवन, प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि राजनीति का असली अर्थ जनसेवा, गरीबों के आंसू पोंछना और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, न कि सत्ता का प्रदर्शन करना।

छात्रों और युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति का कद उसकी तारीफया बुराई से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। हमें पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते रहना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि श्परहित सरिस धर्म नहीं भाईश्कृअर्थात दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ा धर्म है।

इस अवसर पर जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शाला के प्राचार्य, शिक्षकगण, ग्रामीण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मुआवजा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने के दिए निर्देश...

मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम, हाथी प्रभावित परिवारों के मुआवजा प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा हाथियों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन, विद्युत, राजस्व, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मानव-हाथी द्वंद्व की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने वन विभाग की हाथी निगरानी टीमों को पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि हाथियों को हरसंभव प्रयास कर रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाए, ताकि जनहानि एवं अन्य

दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि हाथी प्रभावित गांवों में समय पर सूचना पहुंचाना तथा ग्रामीणों को सतर्क रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भीड़ नियंत्रण की स्थिति में पुलिस एवं वन विभाग को आपसी समन्वय के साथ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में हाथियों से हुई जनहानि, फसल क्षति, मकान एवं अन्य संपत्ति नुकसान से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होने देने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाने के लिए विशेष ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। इसके माध्यम से प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, लंबित मामलों की समीक्षा तथा भुगतान की प्रगति पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

कलेक्टर ने हाथी विचरण क्षेत्रों से गुजरने वाली 11 केवी विद्युत लाइनों के लो-हैंगिंग प्वाइंट्स का तत्काल सर्वे कर उन्हें मानक ऊंचाई तक सुधारने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्युत तारों के संपर्क में आने से किसी भी हाथी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वन एवं विद्युत विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर झूलते तारों, क्षतिग्रस्त विद्युत खंभों तथा कम ऊंचाई वाली विद्युत लाइनों में शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध विद्युत हुकिंग तथा खेतों में करंटयुक्त तार लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में हाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक पक्के आवास स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों को ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण कर शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

कलेक्टर दुदावत ने भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चिन्हित हाथी गलियारों में हाथियों के सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित एलीफेंट कॉरिडोर में किसी भी विकास अथवा निर्माण कार्य से पूर्व वन विभाग से आवश्यक अनुमति एवं अभिमत प्राप्त किया जाए तथा विकास योजनाओं में हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों को किसी भी प्रकार से बाधित न किया जाए। उन्होंने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान भी हाथियों के सुरक्षित आवागमन का विशेष ध्यान रखने को कहा।

ऋषभ शेट्टी की द प्राइड ऑफ भारत से जुड़ीं भूमि पेडनेकर

वीर योद्धा रानी बेलावड़ी मल्लम्मा की किरदार से मचाएंगी तहलका

ऋषभ शेट्टी अपनी आगामी फिल्म द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर चर्चा में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय पहले से अहम किरदारों में शामिल थे। ताजा अपडेट है कि एक और बालीवुड अभिनेत्री इस परियोजना का हिस्सा बन गई हैं, जो भूमि पेडनेकर हैं। ये पहला मौका होगा, जब फैंस उन्हें दक्षिण सिनेमा की फिल्म में डेब्यू करते हुए देखेंगे।

मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर आधिकारि पोस्ट साझा करते हुए भूमि के परियोजना में शामिल होने की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि अभिनेत्री फिल्म में कर्नाटक की वीर योद्धा रानी बेलावड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाएंगी, जिन्हें उनकी बहादुरी और अटूट साहस के लिए जाना जाता है।

वहीं शेफाली शाह छत्रपति की मां राजमाता जीजाबाई का किरदार निभाएंगी।

इस फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह कर रहे हैं और संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

ऋषि विरमानी द्वारा लिखित, द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग को 2028 में और दूसरे भाग को 2029 में रिलीज किया जा सकता है।

इसकी शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू होने वाली है, जिसका ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में फिल्माया जाएगा। वहीं व्यापक पूर्व-निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। खबरों के अनुसार, फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है।

एक बार फिर देश का नाम रोशन करेंगी मानुषी छिल्लर, कॉमनवेल्थ गेम्स में देंगी खास परफॉमेंस

मानुषी छिल्लर ने हमेशा भारत को ग्रेस और आत्मविश्वास के साथ रिप्रेजेंट किया है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद से ही वह देश का एक ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की पहचान को आगे बढ़ाया है। अब वे एक बार फिर भारत का नाम ग्लोबल लेवल पर चमकाने वाली हैं।

हैंडओवर सेरेमनी में करेंगी परफॉर्म

एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स हैंडओवर सेरेमनी में लाइव परफॉर्म करने वाली इकलौती भारतीय एक्ट्रेस होंगी। यह खास इवेंट 2 अगस्त को ग्लासगो के OVO हाइड्रो में होगा।

इस अनाउंसमेंट में मानुषी के सफर को खास तौर पर सराहा गया है- मिस वर्ल्ड बनने से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच तक पहुंचने तक। उनकी यह परफॉर्मेंस इस सेरेमनी का एक बड़ा आकर्षण होगी, जो 'रोड टू अहमदाबाद 2030' की शुरुआत को भी दर्शाएगी, जो अगला होस्ट सिटी है।

इकलौती भारतीय एक्ट्रेस होंगी मानुषी

कॉमनवेल्थ गेम्स की यह हैंडओवर सेरेमनी दुनियाभर में देखी जाएगी, जिसमें म्यूजिक, कल्चर और एंटरटेनमेंट के जरिए ग्लासगो 2026 से अहमदाबाद 2030 तक का सफर दिखाया जाएगा।

ऐसे में इकलौती भारतीय एक्ट्रेस के तौर पर मानुषी की मौजूदगी और भी खास बन जाती है। इस खास मौके के साथ मानुषी छिल्लर अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ रही हैं। अब फैंस को उनकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार है, जहां वह एक बार फिर गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।

ममता कुलकर्णी के लोकप्रिय गाने का बना रीमेक, राणाजी 2.0 में इस बार माहिरा शर्मा ने लगाई डांस का तड़का

बॉलीवुड में लोकप्रिय गानों का रीमेक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अब 90 के दशक का चर्चित गाना मुझको राणा जी माफकरना रीमेक बनकर लौटा है, जिसे राणाजी 2.0 नाम दिया गया है। इसमें माहिरा शर्मा अपने डांस का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं।

रीमेक वर्जन में भी आवाज अलका याग्निक और इला अरुण की है, लेकिन इसका संगीत तनिष्क बागची ने दिया है। कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने की है, जबकि निर्माता कुमारी तौरानी हैं।

टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर राणाजी 2.0 गाना रिलीज हुआ है, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

एक यूजर ने लिखा, राणा जी, सिर्फएक हो सकते हैं और वो अमरीश पुरी हैं।

एक अन्य यूजर ने लिखा, बार-बार सिर्फ अलका याग्निक के गानों का रीमेक क्यों बनाया जा रहा है?

बता दें, असल में यह गाना शाहरुख खान और सलमान खान अभिनीत फिल्म करण अर्जुन (1995) का है, जिसे ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था।

इब्राहिम के साथ पलक तिवारी की डेटिंग की अफवाहों पर क्या बोले पिता राजा चौधरी? श्वेता को लेकर कही ये बात

अभिनेत्री पलक तिवारी के पिता राजा चौधरी ने उनके और इब्राहिम अली खान की डेटिंग की अफवाहों पर बात की है। उन्होंने बेटी के सलमान खान के साथ काम करने के बारे में भी बात की है।

अभिनेत्री पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान कई बार एक-साथ स्पॉट किए गए हैं। दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा है। इस मामले पर पलक तिवारी के पिता और एक्टर राजा चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी श्वेता तिवारी को लेकर भी बात की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है?

उसकी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में राजा से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी बेटी के सलमान खान के साथ काम करने और अपना नाम बनाने पर गर्व है। इस पर उन्होंने कहा 'मुझे नहीं पता (कि मुझे गर्व है या नहीं)। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वह कहां है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, कहां रह रही है, किसके साथ रह रही है और किसके साथ काम कर रही है। मैं जानना भी नहीं चाहता, जब तक कि वह खुद आकर मुझे न बताए कि डैड, ऐसा हो रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए 24/7 मौजूद हूं। उसकी जिंदगी में मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।'

डेटिंग की अफवाहों पर क्या बोले राजा?

इसके बाद राजा से पूछा गया कि पलक और इब्राहिम के डेटिंग की अफवाहें सुनकर उन्हें कैसा लगता है। इस पर एक्टर ने कहा 'इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे साथ हैं या नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी जंगल में अकेले तो नहीं रह रही है कि यह कोई बड़ी बात हो। एक पिता के लिए यह मायने रखता है कि बेटी ने रिश्ता बनाए रखा है या नहीं। उसकी मां से पूछिए कि उन्हें कैसा लगता है। मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं तो बस बायोलॉजिकल पिता हूं, मुझे यही बताया गया था। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं कैसा महसूस करूं?'

श्वेता और राजा का रिश्ता

आपको बता दें कि राजा और श्वेता की शादी 1998 में हुई थी और 2000 में उनकी बेटी पलक का जन्म हुआ। श्वेता ने 2007 में तलाक के लिए अर्जी दी और आरोप लगाया कि राजा की शराब की लत के कारण उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में राजा ने इन आरोपों से इनकार किया। 2012 में उनका तलाक हो गया।

खाने में तीखापन लाती है लाल मिर्च, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

लाल मिर्च का इस्तेमाल भारतीय रसोई में बहुत आम है। इसका उपयोग खाने को तीखा और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लाल मिर्च में कई ऐसे गुण भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको लाल मिर्च के कुछ ऐसे ही लाभों के बारे में बताएंगे, जो आपको हैरान कर देंगे।

वजन कम करने में है मददगार

लाल मिर्च में एक खास तत्व होता है, जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। यह तत्व शरीर की गर्मी को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में सहायक होता है।

इसके अलावा यह भूख को कम करता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन नियंत्रित कर सकते हैं।

नियमित रूप से लाल मिर्च का सेवन करने से आप अपने वजन घटाने के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं।

पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में है सहायक

लाल मिर्च का सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आंतरिक अंगों को सक्रिय करके पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है।

इसके अलावा यह कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करती है।

लाल मिर्च में मौजूद तत्व पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं और शरीर को साफकरने में सहायक होते हैं। इस प्रकार लाल मिर्च का सेवन पाचन तंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है प्रभावी

लाल मिर्च एक जरूरी विटामिन का अच्छा स्रोत होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।

यह शरीर की सुरक्षा बढ़ाकर संक्रमण और बीमारियों से बचाव करता है। नियमित रूप से लाल मिर्च का सेवन करने से आप सर्दी-खांसी जैसी आम समस्याओं से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

इसके अलावा इसमें मौजूद गुण भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

खून के प्रवाह को बेहतर बनाने में है कारगर

लाल मिर्च खून के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें मौजूद तत्व रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे खून का प्रवाह सुचारू होता है।

यह तत्व शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाने में सहायक होता है।

इसके अलावा यह तत्व थक्का बनने की संभावना को कम करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा भी घटता है।

दूरस्थ ग्राम रामपुर को मिली मजबूत मोबाइल नेटवर्क सुविधा, नए टॉवर से डिजिटल सेवाओं का होगा विस्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। जिले के उसूर विकासखंड अंतर्गत ग्राम रामपुर (ग्राम पंचायत पुजारी कांकेर) में नए मोबाइल नेटवर्क टॉवर का सफलतापूर्वक संचालन प्रारंभ हो गया है। वर्षों से कमजोर मोबाइल नेटवर्क और सीमित संचार सुविधाओं का सामना कर रहे ग्रामीणों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टॉवर के चालू होने से अब रामपुर एवं आसपास के गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से उपलब्ध होंगी।

बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में अब संचार व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। मोबाइल टॉवर की स्थापना से ग्रामीणों को मोबाइल कॉल, इंटरनेट उपयोग एवं डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त होगा, जिससे दैनिक जीवन और अधिक सुविधाजनक बनेगा।

नई नेटवर्क सुविधा का लाभ विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों को मिलेगा। अब ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, सरकारी पोर्टलों पर आवेदन, ई-गवर्नेंस सेवाओं तथा अन्य इंटरनेट आधारित सुविधाओं का उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक सरल और तेज़ होगा।

बेहतर नेटवर्क उपलब्ध होने से आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क स्थापित करना भी आसान होगा। साथ ही ग्रामीण अपने परिजनों एवं अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों से निर्बाध रूप से संवाद कर सकेंगे। मजबूत मोबाइल कनेक्टिविटी से क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी समय पर ग्रामीणों तक पहुंचेगा।

स्थानीय ग्रामीणों ने मोबाइल टॉवर के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि लंबे समय से बेहतर नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

ग्राम रामपुर में स्थापित यह मोबाइल टॉवर केवल संचार सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक आधुनिक संचार सुविधाएं पहुंचाने की यह पहल ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगी।

खास-खबर

सीएम हेल्पलाईन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर हुई तत्काल कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायत के आधार पर श्रम विभाग की त्वरित कार्रवाई से 103 मजदूरों को उनका लंबित वेतन मात्र दो दिनों के भीतर दिलाया गया। श्रम पदाधिकारी गरियाबन्द सुश्री जयंती बसंल ने बताया कि विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम कुंडेल निवासी नोमेन्द्र कुमार जोशी ने इस संबंध में सीएम हेल्पलाईन 1076 के माध्यम से शिकायत दर्ज किया था। जिसमें स्वयं के साथ अन्य 102 मजदूरों द्वारा मजदूरी भुगतान प्राप्त नहीं होने के संबंध शिकायत की गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर श्रम विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग एवं नियोक्ता से संपर्क कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की। विभागीय प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी मजदूरों का लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया।

छापरटोली में सोलर हाई मास्ट लाइट स्थापना कार्य का भूमि पूजन संपन्न

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ सुदृढ़ विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विद्युत अधोसंरचना के विकास, नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना, विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी दिशा में जशपुर जिले में भी विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। आवश्यकता के अनुरूप नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं, वहीं कुनकुरी विकासखंड के हर्राडांड़ में 400 केवी सब-स्टेशन सहित अन्य विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन प्रयासों से जिले में विद्युत आपूर्ति और अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी हो रही है। इसी क्रम में कुनकुरी विकासखंड की ग्राम पंचायत जामचुंवा के छापरटोली में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सोलर हाई मास्ट लाइट स्थापना कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया।

प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का कार्य तेज़ी के साथ जारी हैं। राज्य में 28 जुलाई की स्थिति में राज्य के 39.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 80 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को अब तक 9.95 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.38 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती- किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है।

राज्य में लक्ष्य का 80 प्रतिशत बोनी पूर्ण

लक्ष्य का 80 प्रतिशत क्षेत्रों में बोनी पूर्ण

राज्य में अब तक 39.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल आदि की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इस खरीफसीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने बताया कि 28 जुलाई सुबह तक की स्थिति में प्रदेश में अब तक 447.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है।

किसानों को 4.38 लाख क्विंटल बीज वितरित: अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2026 के लिए बीज निगम द्वारा प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.75 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.38 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो मांग का 88 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में 4.31 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था।

14.95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण

प्रदेश में इस खरीफसीजन में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 14.95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 9.95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 64 प्रतिशत है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को खेती-किसानी में सहूलियते हो इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्प कालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे है। चालू खरीफसीजन 2026 के लिए 27 जुलाई की स्थिति में 6931.51 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 5691.72 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया था। इस वर्ष किसानों को 8800 करोड़ रूपए ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

एटीआर मॉड्यूल का प्रशिक्षण सम्पन्न, पंचायतों में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली होगी और अधिक पारदर्शी

श्रीकंचनपथ न्यूज

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर कार्यालय के अधिकारियों की आठ सदस्यीय दल ने आज जिला पंचायत गरियाबंद के सभाकक्ष में जनपद पंचायत गरियाबंद, फिंगेश्वर, छुरा, मैनपुर एवं देवभोग के पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एटीआर मॉड्यूल का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

राज्य संपरीक्षा कार्यालय के क्षेत्रीय उपसंचालक अविनाश तिवारी, सहायक संचालक कदम सिंह सिदार, सतीश चौधरी, सौरभ तिग्गा, ज्येष्ठ संपरीक्षक प्रियंका मरावी, सहायक संपरीक्षक रोहित दास, संजीव भगत एवं फैजान अहमद ने प्रशिक्षण में पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं निर्धारित समय पर कैसे किया जाना इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एटीआर मॉड्यूल के संचालन, ऑनलाइन प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया तथा मॉड्यूल से संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं के बारे में बताया गया। साथ ही प्रतिवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों के संधारण, डेटा की शुद्धता तथा समय-सीमा के भीतर जानकारी अपलोड करने के संबंध में भी विस्तार से समझाया गया।

प्रशिक्षण में मॉड्यूल के माध्यम से कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं प्रगति की प्रभावी समीक्षा की उपयोगिता पर भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों को मॉड्यूल के संचालन का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया तथा उनकी जिज्ञासाओं एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान भी अधिकारियों द्वारा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एटीआर मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग से पंचायत स्तर पर कार्यों की प्रगति का समयबद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध होगा।

चारामा में नेचर पार्क के सामने ट्री एटीएम का किया गया स्थापना

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने एवं जनसहभागिता से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वनमंडल कांकेर के अंतर्गत चारामा परिक्षेत्र में नेचर पार्क जैसाकर्रा चारामा के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ट्री एटीएम की स्थापना की गई है। इस अभिनव पहल के माध्यम से वर्षा ऋतु के वर्तमान रोपण सत्र में क्षेत्र के किसान, ग्रामवासी, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं इच्छुक नागरिकों को पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

ट्री एटीएम में स्थानीय जलवायु के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधे प्राप्त

कर उन्हें अपने खेतों, घरों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर रोपित कर सकते हैं। चारामा परिक्षेत्र का यह ट्री एटीएम वन विभाग की जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल है, जो वृक्षारोपण को सरल, सुलभ एवं जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर प्रदेशभर में जागरूकता, जांच और टीकाकरण अभियान को मिली गति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुदृढ़ और जनकेंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा सामुदायिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण से बचाव, समय पर जांच, टीकाकरण तथा सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, समय पर रोगों की पहचान तथा जनजागरूकता को स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता बनाया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों की रोकथाम एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सके।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग की गई तथा स्वास्थ्य कर्मियों एवं उच्च जोखिम वाले हितग्राहियों का हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में परामर्श सत्र, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम और प्रचार-प्रसार गतिविधियों के माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष अभियान चलाकर आमजन को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा ने हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण, उसके बचाव एवं उपचार की जानकारी देते हुए सुरक्षित इंजेक्शन के उपयोग, सुरक्षित रक्ताधान तथा हेपेटाइटिस ए एवं ई से बचाव के लिए स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

बदलते बस्तर का संदेश लेकर दिल्ली रवाना हुआ बस्तर का प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए जताएंगे आभार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बदलते बस्तर का संदेश लेकर दिल्ली रवाना हुआ बस्तर का प्रतिनिधिमंडलबस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और बदलते बस्तर की नई तस्वीर को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बस्तर के परगना मांझी, चालाकी, समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम-2026 के प्रसिद्ध जनजातीय युवा कलाकार, जनजातीय समाज प्रतिनिधि तथा बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं सहित 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से 30 जुलाई 2026 को मुलाकात करेगा तथा बस्तर की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था से उन्हें अवगत कराएगा।

बस्तर की नई पहचान शांति, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी

प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के प्रति बस्तरवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए संदेश देंगे कि अब बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि शांति, विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी और नई उम्मीदों से भी जुड़ चुकी है। बस्तर के युवा पूरे देश को बताएंगे कि नया बस्तर अवसरों, आत्मविश्वास और प्रगति का बस्तर है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष यह संदेश भी रखेंगे कि आज का बस्तर हिंसा और भय की पहचान से निकलकर शांति, विकास और विश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। बस्तर के युवा अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभा के बल पर देशभर में नई पहचान बना रहे हैं।

वे राष्ट्रपति को बताएंगे कि शासन की विकासोन्मुखी पहल और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक सफ्लता मिली है, जिससे बस्तर में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और जनजीवन को नई गति मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली रवाना हो रहे बस्तर के परगना मांझी, चालाकी, समाज प्रमुखों एवं युवा प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल केवल बस्तर का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक बस्तर की लोकसंस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक मूल्यों की गूंज पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आज का बस्तर बदल रहा है। कभी नक्सलवाद की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब शांति, विकास, शिक्षा, पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान बना रहा है।

हमारे युवा देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था तक पहुंचकर इस सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रपति के समक्ष बस्तरवासियों की ओर से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिले सहयोग और देश के नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करेगा। यह यात्रा देश को यह संदेश देगी कि बस्तर अब भय का नहीं, बल्कि विश्वास, विकास, संस्कृति और नए अवसरों का बस्तर है।

धरमपुर में महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण (हब) द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमपुर में सहारा महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, मासिक धर्म स्वच्छता, बाल विवाह की रोकथाम, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित महिलाओं व विद्यार्थियों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098, 181 एवं 112 की जानकारी दी गई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें। महतारी वंदन योजना एवं अन्य महिला हितैषी योजनाओं के विषय में भी अवगत कराया गया।

खास खबर

इंडक्शन फर्नेस में बॉयलिंग से 4 श्रमिक झुलसे, दो की हालत गंभीर

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर स्टील प्लांट में हादसा हो गया। मां शिवा स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस में बॉयलिंग होने से चार श्रमिक झुलस गए। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार सुबह करीब 7 बजे हुई। रोज की तरह श्रमिक प्लांट में काम कर रहे थे। इसी दौरान इंडक्शन फर्नेस में अचानक बॉयलिंग होने से प्रमोद सोनी, चौखर सिंह, शनि सिंह और गुड्डू इसकी चपेट में आकर झुलस गए.हादसे के बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिंदल फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें दो श्रमिक गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस और औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

रायपुर पुलिस ने पकड़ी फर्जी महिला जमानतदार

रायपुर। रायपुर के न्यायालय परिसर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत लेने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। न्यायालय परिसर में फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर आरोपियों की जमानत कराए जाने की शिकायत मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र तारकेश्वर पटेल ने सिविल लाइन थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से न्यायालय में आरोपियों की जमानत ले रही हैं। टीम ने न्यायालय परिसर पहुंचकर मामले की तस्दीक की। इस दौरान तीन महिलाओं को ऋण पुस्तिका में काट-छांट कर जमानत लेते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर अलग-अलग न्यायालयों में आरोपियों की जमानत लेने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने सुनीता देवी राजपूत (70), सरस्वती बाई सोनी (72) और मीना बाई कोरम (52) को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 401/2026 और 402/2026 दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 238 और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।

बैनर-पर्चे लगाने वाले 6 फर्जी माओवादी गिरफ्तार

राजनांदगांव। गढ़चिरौली पुलिस ने पोमके-फुलणार क्षेत्र में माओवादी होने का झूठा आभास देकर बैनर और पर्चे लगाकर दहशत फैलाने के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पोमके-फुलणार से करीब 8 किलोमीटर दूर हिहुर-दोबुर मार्ग पर दो पेड़ों के बीच लाल रंग का बैनर और एक पोस्टर मिला था। उस पर लिखे संदेश का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देश पर विशेष जांच शुरू की गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर छह आरोपियों की पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपियों में जोगा रैनु धुर्वा (40), मालु कांडे धुर्वा (42), दलसु मर्रा तेलामी (50), चैतु डूंगा धुर्वा (53), गणेश देवू आलामी (40) और राजेश दल्लु वड्डे (32) शामिल हैं। सभी आरोपी भामरागढ़ तहसील के विभिन्न गांवों के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

साइबर ठगी में इस्तेमाल म्यूल खाताधारकों पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। साइबर ठगी में प्रयुक्त लेयर-1 (म्यूल) बैंक खातों की पहचान कर 26 खाताधारकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में साइबर ठगी की राशि बैंक खातों में प्राप्त कर अन्य खातों में स्थानांतरित एवं निकासी किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आरोपियों द्वारा अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराकर साइबर अपराध में सहयोग किया जाना पाया गया। आरोपियों के खिलाफधारा 318(2), 318(3), 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा म्यूल बैंक खाताधारकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय तकनीकी सेवा (साइबर) के निर्देशानुसार 21 अप्रैल 2026 से थाना भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत संचालित पंजाब नेशनल बैंक के ऐसे खातों का परीक्षण किया गया जिनका उपयोग साइबर ठगी से संबंधित विभिन्न शिकायतों में किया गया था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि संदिग्ध बैंक खातों में साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि सीधे जमा हुई, जिससे ये खाते लेयर-1 (Mule Account) की श्रेणी में पाए गए। प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 से 2026 के मध्य इन खातों के माध्यम से विभिन्न पीड़ितों से छलपूर्वक प्राप्त धनराशि को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित अथवा आहरित किए जाने के तथ्य सामने आए।

प्रथम दृष्टया यह भी पाया गया कि संबंधित खाताधारकों द्वारा स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल सिम एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराई गईं, जिनका उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने, छिपाने, स्थानांतरित करने तथा उससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया।

उक्त तथ्यों के आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 388/2026 अंतर्गत धारा 318(2), 318(3), 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी 26 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में डिजिटल एवं बैंकिंग साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विवेचना जारी है तथा साइबर ठगी के मास्टरमाइंड एवं अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही है।

उक्त कार्रवाई में थाना भिलाई नगर पुलिस की साइबर टीम, विवेचना अधिकारी एवं थाना स्टाफ द्वारा तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग अभिलेखों का परीक्षण, खाताधारकों की पहचान एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभाई गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल सिम, ओटीपी अथवा इंटरनेट बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं।

किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खाते में धनराशि प्राप्त कर उसे आगे स्थानांतरित करना भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जिसके लिए संबंधित खाताधारक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम पुलिस थाना में संपर्क करें।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

शंकर चौधरी, उम्र 50 वर्ष, कार्तिये साहू, उम्र 24 वर्ष, रूपेश कुमार देवांगन, उम्र 20 वर्ष, अनील कुमार शर्मा, उम्र 58 वर्ष, कमल दास मानिकपुरी, उम्र 33 वर्ष, पुरुषोत्तम भारती, उम्र 25 वर्ष, राकेश कुमार निर्मलकर, उम्र 33 वर्ष, राहुल मेश्राम, उम्र 25 वर्ष, हिमांशु यादव, उम्र 23 वर्ष, अरविंद पासवान, उम्र 20 वर्ष, आदित्य कुमार वर्मा, उम्र 23 वर्ष, शैलेन्द्र विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, मोह. कमाल, उम्र 28 वर्ष, महेन्द्र कुमार साहू, उम्र 26 वर्ष, दुर्गा प्रसाद ठाकुर, सचिन मेश्राम, उम्र 44 वर्ष, नारायण देवांगन, उम्र 27 वर्ष, आशुतोष मिश्रा, उम्र 24 वर्ष, अभिषेक कुमार वर्मा, उम्र 25 वर्ष, जितेन्द्र हरिश कुमार, उम्र 24 वर्ष, प्रभावति हरिजन, उम्र 50 वर्ष, गीता लाजेवार, उम्र 45 वर्ष, सतविन्दर कौर, उम्र 30 वर्ष, श्रुति वर्मा, उम्र 28 वर्ष, प्रेम शीला चौधरी, उम्र 27 वर्ष, अंकिता बंजारे, उम्र 22 वर्ष।

कार का कांच तोड़कर 4.90 लाख चुराए

उत्सव शोरूम के सामने खड़ी गाड़ी सीसीटीवी में संदिग्ध बाइक सवार नजर आया

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग में दिनदहाड़े कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर 4.90 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। बदमाश कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपी कारोबारी का घर से ही पीछा कर रहा था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध बाइक सवार भी नजर आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक मुक्त नगर निवासी प्रमोद महेश्वरी की कोडहा में 'देव एग्रो इंडस्ट्रीज' के नाम से फैक्ट्री है। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे वे अपने घर से 4.90 लाख रुपए लेकर स्विफ्ट कार से निकले थे। रकम एक काले रंग के बैग में रखी थी, जिस पर 'जयश्री साल्वेंट्स' लिखा था। यह राशि उन्हें एक पार्टी को भुगतान के लिए ले जानी थी।

सुबह करीब 9 बजे प्रमोद ने पोटिया रोड स्थित उत्सव शोरूम के सामने कार खड़ी की और उसे लॉक कर अपनी दूसरी बाइक से नया पारा, दुर्ग चले गए। वहां वे अपने दोस्त रितेश साहू की बारदाना दुकान पहुंचे।

इसके बाद इंदिरा मार्केट स्थित मनमोहन स्वीट्स में चाय पी। वापस लौटते समय उन्हें उत्सव शोरूम के संचालक अमरजीत सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि कार का बाईं ओर का अगला शीशा टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर प्रमोद ने देखा कि कार से नकदी से भरा बैग गायब था।

सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध

घटना की सूचना मिलने पर पुलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी को कारोबारी के पास बड़ी रकम होने की पहले से जानकारी थी। इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि उसने घर से ही प्रमोद का पीछा किया और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया।

बीएसपी में 210 किलो स्कैप कॉपर चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से चल रहे थे फरार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में घुसकर 210 किलो स्कैप कॉपर चोरी करने वाले गिरोह के दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए 210 किलो स्क्रैप कॉपर, जिसकी कीमत करीब 1.26 लाख रुपए है, पहले ही जब्त किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश कुहीकर (34) निवासी कुरूद और प्रीतम कुमार उर्फ पंचू निषाद (31) निवासी मरोदा शामिल हैं।

24 मई को हुई थी वारदात

भिलाई भट्ठी थाना पुलिस के अनुसार, 24 मई 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने भिलाई इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल-03 के पीछे कुछ लोगों को अवैध रूप से प्लांट में घुसकर स्क्रैप कॉपर चोरी करते हुए पकड़ा था। इसके बाद सीआईएसएफ ने भिलाई भट्ठी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

पहले मुख्य आरोपी हुआ था गिरफ्तार

शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी नेमचंद यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 210 किलो स्क्रैप कॉपर बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.26 लाख रुपए आंकी गई। उसे 24 मई को ही कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

हालांकि, घटना में शामिल दो अन्य आरोपी आकाश कुहीकर और प्रीतम कुमार उर्फ पंचू निषाद वारदात के बाद से फरार थे। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। 27 जुलाई को दोनों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

बिना अनुमति प्लांट में घुसे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने बिना अनुमति प्लांट परिसर में प्रवेश कर वहां रखा स्क्रैप कॉपर चोरी करने की कोशिश की थी। इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें देख लिया और कार्रवाई की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुख्य आरोपी नेमचंद यादव के साथ मिलकर भिलाई स्टील प्लांट में घुसकर स्क्रैप कॉपर चोरी की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गरियाबंद में नाला पार करते अधेड़ बहा, मौत 5 किमी दूर मिला शव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बीच गरियाबंद में उफनते सरगी नाला को पार करते समय सहसपुर निवासी थनवार यादव (55) बह गया। लोगों के मुताबिक वह नशे में था। करीब 5 किमी दूर खुटेरी गांव में उसका शव मिला। वहीं, सिकासार बांध से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पैरी नदी किनारे अलर्ट जारी किया गया है। इधर, मंगलवार को बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 3 ग्रामीण, सूरजपुर में एक किसान और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में एक महिला मजदूर की जान चली गई। इन हादसों में 11 लोग घायल हुए हैं। उधर, सारंगढ़-बरमकेला के लाट नाले में बही कार में सवार पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी का दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।

सुपेला में रेलवे ट्रैक पर खड़ी बीटीपीएन वैगन पर चढ़ा युवक, ओएचई की चपेट में आया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सुपेला अंडरब्रिज के पास मंगलवार दोपहर बाद एक युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ी बीटीपीएन वैगन पर चढ़ गया। इससे युवक ओएचई लाइन की चपेट में आया और गिर गया। घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आरपीएफ व पुलिस के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके से डायल 112 को कॉल किया गया। सूचना मिलने के लगभग 40 मिनट बाद एंबुलेंस पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया।

मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम गणेश गुप्ता निवासी गौतम नगर सुपेला बताया जा रहा है। सुपेला अंडरब्रिज के पास रेलवे ट्रेक पर

बीटीपीएन वैगन वाली गुड्स ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने के कारण खड़ी थी। बताया जा रहा है कि वैगन में डीजल भरा हुआ था। इस दौरान गणेश गुप्ता अचानक एक वैगन की सीड़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर पहुंच ओएचई के चपेट में आने से जोरदार झटके के साथ नीचे गिरा।

ओएचई के झटके के कारण युवक बुरी तरह झुलस गया। उसका शरीर जगह जगह से जल चुका था और नीचे गिरने के बाद छटपटाने लगा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। झुलया युवक बार बार अस्पताल ले जाने की बात कर रहा था। मौके से लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पुलिस व आरपीएफ के जवान पहुंचे। इस दौरान युवक ने अपना नाम भी खुद ही बताया। कुछ देर बाद जैसे ही एंबुलेंस पहुंची तो आसपास के कुछ युवकों की मदद से झुलसे गणेश गुप्ता को एंबुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया। शास्त्री अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है।

नशे में होने की आशंका

बताया जा रहा है युवक नशे में था और नशे की हालत में ही वैगन पर चढ़कर ओएचई के संपर्क में आया। कुछ लोगों ने उसे वैगन पर चढ़ते हुए देखा था। बताया यह भी जा रहा है कि गणेश गुप्ता अपने दो साथियों के साथ रेलवे ट्रैक के पास ही शराब का शेवन कर रहा था।

इसके बाद अचानक व बीटीपीएन वैगन पर चढ़ गया और करंट की चपेट में आ गया। यह देख ट्रेन के गार्ड ने आवाज भी लगाई लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। गणेश गुप्ता को मौके पर छोड़ उसके साथी वहां से भाग गए।

धान की रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली महिला मजदूर की मौत

मरवाही। मरवाही क्षेत्र के ग्राम मड़वाही में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार किया गया। जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। खेत में धान का रोपा लगाने गए आठ मजदूरों में से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच मजदूर घायल हो गए। दो अन्य मजदूर सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार घटना सिवनी चौकी अंतर्गत ग्राम मड़वाही की है। सभी मजदूर गांव के एक किसान के खेत में धान का रोपा लगाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से श्यामबाई लोधाम (32 वर्ष), पति रमेश लोधाम, निवासी ग्राम मड़वाही की मौके पर ही मौत हो गई।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बेमेतरा

शीतला मंदिर के पास सिंघौरी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

E-mail Id:- eeres.bemetara@gmail.com

क्र./1889/का.अभि/वलेलि/ग्रा.यां.सेवा/2026-27 बेमेतरा, दिनांक 27/07/2026

संक्षिप्त ई-जोनल निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 07 (द्वितीय आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत (लोक निर्माण विभाग में) ''द'' एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शित सिविल कार्य हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर द्वारा निर्माण एवं संधारण कार्य हेतु दर अनुसूची जो दिनांक 01.11.2021 एवं विद्युत कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 में प्रचलित एवं अद्यतन संशोधित दरों पर प्रतिशत दर एवं ट्यूब वेल कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिनांक 01.06.2020 में प्रचलित एवं अद्यतन संशोधित दरों पर विकासखण्ड बेमेतरा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों हेतु स्वीकृत 30.00 लाख लागत तक के निर्माण कार्य हेतु जोन क्र.-01, जोन क्र.-02, जोन क्र.-03, जोन क्र.-04 एवं जोन क्र.-05, विकासखण्ड बेरला के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों हेतु स्वीकृत 30.00 लाख लागत तक के निर्माण कार्य हेतु जोन क्र.-02 एवं विकासखण्ड साजा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों हेतु स्वीकृत 30.00 लाख लागत तक के निर्माण कार्य हेतु जोन क्र.-01, जोन क्र.-02, जोन क्र.-03, जोन क्र.-04 एवं जोन क्र.-05 प्रत्येक जोन हेतु 35.00 लाख रूपये का जोनल ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्ते व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा विभागीय वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 28.07.2026 से देखी/डाउनलोड की जा सकती है एवं निविदा प्राप्ती की अंतिम तिथि 06.08.2026 तथा निविदायें दिनांक 13.08.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे खोली जावेगी।

(महाजन बांधडे)
कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-बेमेतरा
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

जी-262702400/3

दमाऊधारा में दोस्तों संग घूमने आया भिलाई का छात्र गहरे पानी में डूबा

सक्ती। सक्ती जिले के नगरदा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दमाऊधारा में घूमने आए भिलाई निवासी 20 वर्षीय छात्र का पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने का मामला सामने आया है। प्रतीक कंवर (20 वर्ष) निवासी भिलाई अपने पांच दोस्तों के साथ सक्ती जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने आया था। सभी दोस्त सोमवार को रैनखोल पर्यटन स्थल घूमने के बाद मंगलवार सुबह दमाऊधारा पहुंचे थे। दमाऊधारा पहुंचने के बाद समूह के चार युवक ऊंचाई वाले हिस्से में चले गए, जबकि दो साथी नीचे ही रुके रहे। लौटते समय अचानक प्रतीक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। टीम ने कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस का जज़्बा ही सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक विजय में पुलिस जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को बताया ऐतिहासिक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायपुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा, विश्वास और सुशासन की सबसे मजबूत आधारशिला है। पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर, हर मौसम और हर चुनौती के बीच दिन-रात जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। उनके त्याग, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही आम नागरिक अपने घरों में निश्चिंत होकर जीवन जी पाते हैं। ऐसे समर्पित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित 'जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल के मनोबल और सेवा भावना का सम्मान है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के साहसी, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के बीच उपस्थित होकर विशेष आत्मीयता और गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन जिस निष्ठा से करते हैं, वह समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायक उप निरीक्षक ज्ञानेश्वरी यादव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने 199 किलोग्राम भार उठाकर न केवल देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यह सिद्ध किया है कि पुलिस बल के जवान सेवा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अच्छे कार्यों को समाज तक पहुँचाने में मीडिया की बड़ी भूमिका: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह समाज के सकारात्मक प्रयासों को सामने लाकर जनविश्वास को मजबूत करता है। पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और सेवा भावना को समाज के सामने लाने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और युवाओं को भी राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता समाज में विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करती है।

पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान: 'जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026' के अंतर्गत पुलिसिंग में नवाचार, सामुदायिक पुलिसिंग, संवाद से समाधान, सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ई-मालखाना प्रबंधन, पिंक पेट्रोल यूनिट, महिला सुरक्षा, वूमेन हेल्पलाइन, साइबर अपराध नियंत्रण, अनुसंधान एवं अन्वेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार आर. कृष्णा दास, रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित अन्य अधिकारीगण, पुलिसकर्मी एवं उनके परिवारजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

नक्सलवाद पर निर्णायक विजय में पुलिस बल की भूमिका ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद ने बस्तर के विकास की गति को बाधित किया। प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण यह क्षेत्र हिंसा और भय के कारण अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज बस्तर विकास, विश्वास और परिवर्तन के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दृढ़ रणनीति तथा राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लोकतंत्र, विकास और मानवता की रक्षा का अभियान था। हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना कठिन जंगलों में अभियान चलाया और प्रदेश को भयमुक्त बनाने का कार्य किया। यह विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अध्याय बनेगी।

जनआकांक्षाओं को समझने का सशक्त माध्यम है मीडिया : डीजीपी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि किसी मीडिया संस्थान द्वारा पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान किया जाना अत्यंत सराहनीय पहल है। पत्रकारिता समाज के सामने आदर्श स्थापित करती है और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें समाज की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सकता है। डीजीपी गौतम ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति से सबसे अधिक राहत उन परिवारों को मिली है, जिनके बेटे, बेटियां, पति या पिता वर्षों तक बस्तर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे थे। यह उपलब्धि पूरे पुलिस बल के साहस, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है।

घायल जवानों के जज़्बे ने दिलाया आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री साय ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें कई बार अस्पतालों में नक्सल मोर्चे पर घायल पुलिस जवानों से मिलने का अवसर मिला। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की सेवा का अदम्य संकल्प दिखाई देता था। वे कहते थे कि स्वस्थ होते ही फिर से मोर्चे पर लौटेंगे और नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही अदम्य जज़्बा आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आया और इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक सफलता प्राप्त कर सका।

राष्ट्रमंडल खेलों में ज्ञानेश्वरी यादव ने रचा इतिहास रजत पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

▶ राजनांदगांव की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराकर प्रदेश को किया गौरवान्वित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में छत्तीसगढ़ की होनहार भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे प्रदेश में हर्ष और गर्व का माहौल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की बेटी ने विश्व मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर न केवल भारत, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सुश्री ज्ञानेश्वरी की सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की बेटियां खेल, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।

ज्ञानेश्वरी यादव की यह सफलता महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायी मिसाल है और यह राज्य की हजारों युवतियों को बड़े सपने देखने तथा उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों को खेलों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने ज्ञानेश्वरी यादव की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलता की कामना की है। यह उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा, गौरव और उत्साह का प्रतीक बन गई है।

उप मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ, राज्य में खेलों और खिलाड़ियों के लिए बेहतर इको-सिस्टम तैयार करने कर रहे मंथन

समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अहम उपक्रम साबित होगा खेल - अरुण साव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी भागीदारी कर रहे हैं। वे दिनभर अलग-अलग कई सत्रों में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने, खेल प्रतिभाएं को तराशने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने रोडमैप पर मंथन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए खेल एक अहम उपक्रम साबित होगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके मिलेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा और वे एक मजबूत मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए राज्य शासन हर तरह से तैयार है। इसके लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संघों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा खेल अधोसंरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन और खिलाड़ियों के लिए उपलब्धता की सुदृढ़ व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।

श्री साव ने श्विजन टू विक्ट्रीश् थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में श्नेतृत्व, खेल प्रोत्साहन और प्रतिभा खोजश् सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के बीच होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य में बेहतर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में खेल संघों के गठन, उनके व्यवस्थित व मजबूत ढांचे, नियमित गतिविधियों और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आज यहां होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने राज्य शासन द्वारा किए जा रहे आयोजनों और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 150 करोड़ रुपए से अधिक के खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

कॉन्क्लेव के पहले सत्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान सुश्री किरण पिस्दा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। राज्य में पहली बार हो रहे इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव से खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने यहां रोडमैप तैयार होगा, जिसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिलेगा।

कॉन्क्लेव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान, ओलंपियन जिन्शन जॉनसन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया सहित अनेक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, सभी जिलों के खेल अधिकारी, प्रशिक्षक, पदक विजेता खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे।

सहकारिता को पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री कश्यप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण एवं उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभाग की 16 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं और मैदानी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मंत्री कश्यप ने प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में डेयरी तथा मत्स्य सोसाइटियों के कार्य प्रणाली को सक्रिय करने का निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छत्तीसगढ़ में दुग्ध सोसाइटियों को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एओयू के तहत कार्ययोजना बनाकर दुग्ध उत्पादन तथा प्रसंस्करण करने के निर्देश दिए। पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से चालू खरीफ सीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 14 लाख से अधिक किसानों को 6932 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया।

ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

जन-शिकायतें एवं ई-ऑफिस

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

धान उपार्जन का अंतिम निराकरण

धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के आदेश दिए गए। बैठक के अंत में मंत्री केदार कश्यप ने सभी विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिये। इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ सी.आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता व पंजीयक सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ़ रमेश शर्मा, मार्कफेड एमडी जितेंद्र शुक्ला, अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के एन कांडे, अपर पंजीयक यू बीएस राठिया, अपर पंजीयक सावित्री भगत व सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के अधिकारीगण तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित रहे।

आजादी के 79 वर्षों बाद भिरागांव को मिली पक्की सड़क की सौगात, ग्रामीणों ने विधायक लता उसेण्डी का जताया आभार

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोण्डागांव। आदिवासी बहुल कोण्डागांव जिले के विकासखंड माकड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरागांव के ग्रामीणों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। आजादी के 79 वर्षों बाद ग्राम पंचायत भिरागांव से सड़क पारा बरकई तक 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। लगभग 703.07 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क कग्रामीणों की बहुप्रतिक्षित मांग थी।

भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक लता उसेण्डी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़क निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जर्जर सड़क के कारण विशेषकर बरसात के मौसम में आवागमन अत्यंत कठिन हो जाता था। विद्यार्थियों, किसानों एवं मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई सड़क बनने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों का आवागमन आसान होगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

इस अवसर पर ग्रामवासियों ने विधायक लता उसेण्डी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप गांव को यह बहुप्रतीक्षित सौगात मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि सड़क निर्माण से भिरागांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा और क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950